प्रकाशनार्थ

पटना, 4 दिसम्बर। सेन्टर फाॅर इन्वायर्नमेंट इनर्जी एंड क्लाइमेट चेन्ज (सीईईसीसी), आद्री द्वारा आद्रभूमि की भेद्यता और जलवायु परिवर्तन पर इसका प्रभाव विषय आज एक वेबीनार का आयोजन किया गया।

इस वेबीनार में सेन्टर फाॅर इन्वायर्नमेंट इनर्जी एंड क्लाइमेट चेन्ज (सीईईसीसी), आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी घोष ने अतिथियों का स्वागत किया और हमारे पर्यावरण में इसके महत्व के बारे में चर्चा की। अपने विशेष संबोधन में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार घोष ने बिहार में आद्रभूमि की भेद्यता और इसकी वर्तमान स्थिति पर विशेष जोर देते हुए हमारे पर्यावरण में आद्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसके संरक्षण के लिए किए गए प्रबंधन के उपायों के बारे में भी उल्लेख किया। उन्होंने काबर झील के बारे में विस्तार से बात की और यह भी बताया कि काबर झील को अक्टूबर 2020 में रमासर सम्मेलन द्वारा महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि काबर झील 1988 से काफी सिकुड़ गई है। उन्होंने आर्द्रभूमि से जुड़ी जैव विविधता के बारे में भी बताया है । डॉ. ए.के. घोष ने आर्द्रभूमि के प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि समुदायों, सरकार और व्यवसाय को आर्द्रभूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एकजुट होना चाहिए।

स्कूल आॅफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के प्रोफेसर डा. मीनाक्षी धोते ने शहरी आद्रभूमि की भेद्यता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने यह भी प्रकाश डाला कि किस प्रकार शहरी विकास गतिविधियों के कारण शहरी क्षेत्र में आद्रभूमि की स्थिति दिनोदिन तेजी से बिगड़ती जा रही है। साथ ही बिहार के शहरों की सुरक्षा के लिए शमन उपाय को लागू किया जाना चाहिए। उसने समझाया कि वेटलैंड्स को पहचान, मैप और उसी के अनुसार बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आजीविका के लिए नारियल के बागान, मछली पकड़ने, बागवानी आदि के लिए आर्द्र भूमि का उपयोग किया जा सकता है। उसने कहा कि शहरीकरण के कारण, आर्द्रभूमि की भूमिका और महत्व की अनदेखी की गई है। उसने यह भी सुझाव दिया कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

साउथ-एशिया, वेटलैंड्स इंटरनेशनल के निदेशक डा. रितेश कुमार ने आद्रभूमि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और कैसे आद्रभूमि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में भूमिका निभा सकते है, के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने बिहार में जलवायु के प्रभाव का भी उल्लेख किया और बताया कि यह कितना प्रभावित कर चुका है।

मुख्य संबोधन में, बिहार सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव, श्री दीपक कुमार सिंह ने बिहार सरकार द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन और प्रासंगिक उपायों के कारण बिगड़ती आद्रभूमि पर अपनी चिन्ताओं को साझा किया। उन्होंने आद्रभूमि की भेद्यता और इसके जीर्णोद्धार के तरीकों के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार और अनुभव भी साझा किए। साथ ही उन्होंने बिहार के नवगठित वेटलैंड्स प्राधिकरण के रोडमैप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी नियोजन बिहार में शासन का सबसे कमजोर हिस्सा है, क्योंकि पटना शहरी अनियोजित शहर बन गया है और आर्द्रभूमि को कवर कर लिया गया है और इसे बस्तियों में बदल दिया गया है। अतिक्रमण, कृषि गतिविधि, भूमि पुनर्ग्रहण, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी और सरकार की उदासीनता श्री दीपक कुमार सिंह द्वारा वर्णित बिहार में आर्द्रभूमि के संरक्षण की प्रमुख चुनौतियां हैं। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई गतिविधियाँ हैंः जल जीवन हरियाली, जलवायु परिवर्तन और आर्द्रभूमि के लिए अलग-अलग विंग का गठन, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम - जैसा कि श्री दीपक कुमार सिंह द्वारा समझाया गया है। उन्होंने यह भी सुझाया कि आमलोगों की सहभागिता के साथ आर्द्र भूमि का संरक्षण करना चाहिए और उसके लिए एक एक्शन प्लान बनना चाहिए।

अंत में निष्कर्ष के रूप में प्रोफेसर अशोक कुमार घोष ने पैनल चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत किया और प्रकाश डाला कि आद्रभूमि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और राज्य में इसके प्रबंधन के साथ शामिल करने के लिए पर्यावरण और आद्रभूमि की भेद्यता का परिप्रेक्ष्य, जो कि रणनीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अंजनी कुमार वर्मा